https://swadeshbhartnews

R.N.I. No. UPHIN/2021/82888

स्वदेश भारत न्यूज

राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक समापार पत्र

जौनपुर से प्रकाशित

जौनपुर
मंगलवार 05 मई 2026
वर्ष : 05 – अंक : 18
पृष्ठ – 4 मूल्य – 5:00 रूपये

संक्षिप्त समाचार

सुनेत्रा पवार ने जीत का इतिहास बनाया, 2.18 लाख वोटों से जीतीं

- 5 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव, इनमें भाजपा 4, कांग्रेस 1 जीती

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे लगभग आ गए हैं। महाराष्ट्र के बारामती सीट से एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने 2 लाख 18 हजार वोटों के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह अंतर भारत के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा है। सुनेत्रा पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी हैं, जिनका 28 जनवरी 2026 को विमान हादसे में निधन हो गया था। बारामती अजित पवार की पारंपरिक सीट रही है। यहां से सुनेत्रा की जीत लगभग तय थी। उनके खिलाफ 22 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे।

महाराष्ट्र के राहुरी सीट से भाजपा के अक्षय कार्डिले जीत गए हैं। भाजपा ने गुजरात, नगालैंड और त्रिपुरा की 1-1 सीट भी जीत ली है। कर्नाटक के बागलकोट में कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। राज्य की दूसरी सीट, दावणगेरे साउथ पर कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। उपचुनाव वाली सभी 7 सीटें पूर्व विधायकों की मौत के कारण खाली हुई थीं। कर्नाटक, नगालैंड और त्रिपुरा में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। गुजरात की लिमखेड़ा और महाराष्ट्र के बारामती और राहुरी सीट पर 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी।

सुनेत्रा पवार ने बारामती में जीत के बाद जनता को धन्यवाद दिया- बारामती में मिली जीत के बाद सुनेत्रा पवार ने जनता का दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह जीत लोगों के भरोसे, प्यार और समर्थन का नतीजा है, जिसे वे हमेशा याद रखेंगे।उन्होंने अजित पवार को याद करते हुए कहा कि यह जीत उनके काम और यादों को समर्पित है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों का आभार जताया और भरोसा दिलाया कि वे सभी वर्गों के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे और जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे।

अमेरिकी सेना ने ईरानी जहाज पाकिस्तान को सौंपा

- चीन से लौटते समय कब्जा किया था; यूएस नेवी होर्मुज में फंसे जहाजों को आज से रेस्क्यू करेगी

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी (एजेंसी)। अमेरिकी सेना ने जब्त किए गए ईरानी जहाज टूस्का को अब पाकिस्तान को सौंप दिया है। अब इस जहाज को उसके क्रू मेंबर के साथ वापस ईरान भेजा जाएगा। यह जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता ने दी।

अमेरिका ने 21 अप्रैल को इस जहाज को पकड़ लिया था। यह चीन से लौट रहा था। तब अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया था कि इस पर हथियार बनाने से जुड़े सामान लाए जा रहे थे। ईरान ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की थी और इसे समुद्री डकैती बताया था।

अमेरिका ने ईरानी जहाज को ऐसे समय पर रिलीज किया है जब कुछ ही घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रम्प ने होर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए नया अभियान शुरू करने का ऐलान किया है।ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर बताया कि कई देशों ने अमेरिका से मदद मांगी है। उनके जहाज यहां फंस गए हैं। ट्रम्प ने इन जहाजों और उनके कर्मचारियों को निर्दोष बताया और कहा कि वे हालात के कारण मुश्किल में फंस गए हैं।

उन्होंने कहा कि अमेरिका इन जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाएगा ताकि वे बिना किसी खतरे के अपना काम जारी रख सकें। यह ऑपरेशन सुबह से शुरू होगा। ट्रम्प ने चेतावनी दी कि अगर इस ऑपरेशन में ईरान ने कोई रुकावट पैदा की तो अमेरिका सख्त जवाब देगा।

पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में कमल लहराया

केरल में कांग्रेस गठबंधन तो तमिलनाडु में टीवीके (विजय) का कमाल

कोलकाता/गुवाहाटी/तिरुवनंतपुरम/पुडुचेरी/चेन्नई (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरलम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 की वोटों की गिनती हुई। रुझानों में बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बना रही है। वह 203 सीटों पर आगे चल रही थी। वहीं, टीएमसी को झटका लगा है और उसने 84 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया और डबल डिजिट में सिमटती दिख रही है। असम में भाजपा, तमिलनाडु में डीएमके, केरल में कांग्रेस आगे थी। पश्चिम बंगाल में 293 सीटों के लिए काउंटिंग हो रही है। वहीं असम की 126 सीटों पर एकतरफा मामला देखने को मिल रहा था और यहां भाजपा 99 सीटों पर आगे चल रही थी।

तमिलनाडु में टीवीके विजय ने चौंकाया, 107 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी- तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके जबरदस्त प्रदर्शन करती नजर आ रही है। उसने सत्ताधारी डीएमके को पछाड़ते हुए 107 सीटों पर बढ़ बनाई हुई है, जबकि डीएमके 71 सीटों पर आगे चल रही थी।

असम में फिर हिमंता सरकार

असम में चुनावी माहौल पूरी तरह गरम था। 126 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हुई थीं।

वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी। दोपहर तक तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई थी। इस बार असम में 85.38 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ था, जो राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा रहा है। मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा और कांग्रेस गठबंधन के बीच था। हिमंता बिस्व सरमा हैट्रिक लगाई। भाजपा यहां एकतरफा जीत की ओर थी।

विजय संदेश में कहा-हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम करेगी: पीएम मोदी

पुडुचेरी में भाजपा की सरकार

पुडुचेरी की 30 सीटों पर मतगणना हुई और यहां बीजेपी 18 और कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही थी।

केरलम में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ सत्ता के करीब थी

केरलम की 140 सीटों पर वोटों की गिनती हुई और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ 100 सीटों पर आगे चल रही थी। वहीं लेफ्ट 35 सीटों के साथ पीछे चल रही है।

असम में कांग्रेस को बड़ा झटका, जोरहाट सीट से चुनाव हारे गौरव गोगोई

असम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के हितेंद्र नाथ ने 23 वोटों के अंतर से हराया कांग्रेस नेता गौरव गोगोई जोरहाट सीट से हराया है। जानकारी के लिए बता दें कि गौरव असम की जोरहाट सीट से चुनाव लड़ रहे थे।

भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पहुंचे ममता और सुवेंदु बाहर भारी फोर्स थी तैनात

बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती जारी थी। एक सीट फालता पर 21 मई को फिर वोटिंग होगी। रुझानों में भाजपा को बहुमत की और थी। भवानीपुर में ममता बनर्जी भाजपा कैंडीडेट सुवेंदु अधिकारी से करीब 7 हजार वोटों से आगे चल रही हैं। दोनों काउंटिंग सेंटर पहुंचे हैं, बाहर भारी फोर्स तैनात थी।

बंगाल में जनसंघ-भाजपा के 72 साल, शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की

- भाजपा पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। 1980 में जनसंघ के नेताओं ने भाजपा बनाई थी। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से थे।
- 1952 में जब जनसंघ ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा तब पार्टी को सिर्फ 9 सीटें मिली थीं। 1967 में एक सीट मिली।
- 2011 तक भाजपा बंगाल के किसी भी विधानसभा चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई।
- पहली बार 2016 में पार्टी को 3 सीटें मिलीं। फिर 2021 में भाजपा 77 सीटों पर जीती और अब अपने दम पर सरकार बनाती दिख रही है।

कोलकाता में भाजपा के समर्थकों का ढोल नगाड़े के साथ जश्न शुरु,झालमुड़ी बांटी

असम और पश्चिम बंगाल चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां तक कि पार्टी के समर्थकों ने अभी से ही ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर समारोह हुआ।

बंगाल में शहर-शहर भाजपा कार्यकर्ताओं का जश्न पश्चिम बंगाल के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भाजपा कार्यकर्ता

जश्न मना रहे हैं। कोलकाता में भाजपा कार्यालय के बाहर 'कमला भोग' व 'झाल मुड़ी' जैसी मिठाइयां बांटी गईं। इसके साथ ही, भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'जय श्री राम' के नारे लगाए। कोलकाता में पार्टी मुख्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे थें और जश्न मना रहे थे। इसी क्रम में स्थानीय नेता नारायण चट्टोपाध्याय 'कमला भोग' व 'झाल मुड़ी' लेकर पहुंचे। उन्होंने सभी को 'झाल मुड़ी' खिलाई।

कोलकाता के साल्ट लेक स्थित भाजपा दफ्तर में जश्न का माहौल है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील बंसल, बिप्लव कुमार देव, मंगल पांडे, राहुल सिन्हा, अमित मालवीय, निशिकांत दुबे, संजय जायसवाल और सतीश गौतम शामिल हैं। कार्यकर्ताओं कार्यालय परिसर में जश्न मनाते नजर आए।

बिहार में फिर टूटा पुल

4.7 किमी लंबा विक्रमशिला सेतु दो हिस्सों में बंटा, सिस्टम पर उठे बड़े सवाल, ट्रैफिक डायवर्ट

पटना (एजेंसी)। बिहार में गंगा नदी पर बना विक्रमशिला सेतु, भागलुर और नवगछिया को जोड़ता है। बिहार के सीमांचल और कोसी क्षेत्र के बीच यह पुल एक महत्वपूर्ण कड़ी है। रविवार रात यह पुल अचानक बीच में से टूट गया। जी हां, पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त होकर गिर गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इसके बाद प्रशासन ने यातायात को दोनों ओर से डायवर्ट कर दिया।

विक्रमशिला पुल एक तरफ से भागलपुर, बांका और झारखंड व दूसरी ओर नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा और मधेपुरा को जोड़ता है। इस क्षेत्र में इस पुल को लाइफलाइन माना जाता है। इस पुल का उद्घाटन साल 2001 में राबड़ी देवी के कार्यकाल में हुआ था।

भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि पुल दो चरणों में ध्वस्त हुआ। पहला हिस्सा रविवार रात 11,55 बजे के आसपास पुल संख्या 133 पर हुआ जबकि आधी रात बाद 1,07 बजे एक पूरा स्पैन गिर गया जिससे 4.7 किलोमीटर लंबा पुल दो हिस्सों में बंट गया। उन्होंने कहा, पहले से अलर्ट जारी होने के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।

भागलपुर की ओर का यातायात मुंगेर की तरफ मोड़ दिया गया है, जबकि दूसरी ओर का ट्रैफिक खगड़िया की ओर डायवर्ट किया गया है।

उन्होंने बताया कि भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार यादव और नवगछिया के एसपी राजेश कुमार घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे और यातायात व्यवस्था संभाली।

बंगाल चुनाव नतीजों के बीच आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

'कानून व्यवस्था संभालना सरकार का काम है'

नईदिल्ली (एजेंसी)। बंगाल विधानसभाव चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। इस बीच ही सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बाद हिंसा की आशंकाओं के मद्देनजर केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि वह राज्य तंत्र से न्यायिक हस्तक्षेप के बिना ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की उम्मीद करता है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि इस स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी न्यायिक आदेश की आवश्यकता नहीं है। सीजेआई की बेंच पीठ ने कहा, राज्य का संचालन राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा किया जाए। वे निर्णय लेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वे (राज्यसरकार) अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। पीठ ने केंद्रीय पुलिस बलों की निरंतर तैनाती के निर्देश देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ये टिप्पणियां तब आईं जब वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरि ने सनातनी संसद की ओर से दायर उस याचिका का जिक्र किया जिसमें मतदान समाप्त होने के बाद भी केंद्रीय बलों की मौजूदगी सुनिश्चित करने और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में निगरानी तंत्र स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

इस याचिका में जल्दी की जरूरत क्या थी?

वकील वी गिरि ने पिछले चुनावों में कथित हिंसा की घटनाओं का हवाला देते हुए अदालत से एहतियाती हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। बता दें कि जब चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और केवल मतगणना शेष थी, तब याचिका की तात्कालिकता को लेकर पीठ आश्वस्त नहीं दिखी। इस मामले में अदालत ने पूछा, चुनाव समाप्त हो चुके हैं, मतगणना चल रही है। ऐसी स्थिति में इतनी तात्कालिकता की क्या आवश्यकता है? अदालत ने यह भी संकेत दिया कि इस प्रकार की शिकायतों के लिए उपयुक्त मंच संबंधित उच्च न्यायालय होगा।

उप्र के दोनों डिप्टी सीएम सवार थे, 10 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

खराब मौसम के चलते लखनऊ-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

नईदिल्ली/भोपाल/लखनऊ/जयपुर/देहरादून (एजेंसी)। खराब मौसम की वजह से दिल्ली से लखनऊ जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई-6476 की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सवार थे। दोनों भोपाल में सुरक्षित उतरे।

यूपी में आंधी-बारिश जारी है। कानपुर, सुल्तानपुर और बाराबंकी समेत 64 जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। पिछले 24 घंटे में जालौन सबसे गर्म शहर रहा। सुल्तानपुर में पेड़ की डाल गिरने से एक की मौत हो गई। राजस्थान के दौसा, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर और हनुमानगढ़ में आंधी के साथ बारिश हुई। ओले भी गिरे। खराब मौसम के कारण तीन लोगों की मौत हो गई।

जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर पेड़ गिरने से 40 मिनट तक जाम रहा। हरियाणा के सिरसा, भिवानी और महेंद्रगढ़ में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। उत्तराखंड के भी 11 जिलों में बारिश हुई। नैनीताल, देहरादून और अल्मोड़ा में ओले भी गिरे।

- **अगले 2 दिन के मौसम का हाल-** राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में आंधी-बारिश का दौर जारी है। आज 13 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। 10 राज्यों में आंधी के साथ बिजली गिरने की आशंका है।
- **5 मई:** जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश के साथ बिजली गिरने का अनुमान है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट है।
- असम, मेघालय और अरुणाचल में कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान है।
- **6 मई:** पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश होगी। यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में बारिश के साथ बिजली गिरने का अनुमान है।

यूपी में आंधी-तूफान, पानी की टंकी टूटकर लटकी,शादी का मंडप उड़ा, 22 जिलों में तेज बरसात; 3 की मौत- यूपी में आंधी-बारिश का दौर जारी है। सोमवार सुबह अयोध्या, सीतापुर और बाराबंकी में ओले गिरे। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर समेत 22 जिलों में आंधी के बाद बारिश हुई।लखनऊ में तूफान के साथ करीब डेढ़ घंटे तक पानी बरसा। यहां सुबह 8.20 बजे अचानक मौसम बदला। दिन में रात जैसा अंधेरा छा गया। फिर बिजली कड़कने लगी। इसके बाद जोरदार बारिश हुई।बारिश और तूफान से पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए। कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। नाले उफना गए। खराब मौसम की वजह से दिल्ली से लखनऊ जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई-6476 की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सवार थे।लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान ने तीन बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं और खराब विजिबिलिटी के चलते लैंडिंग नहीं हो सकी।

सम्पादकीय

आग का सिलसिला

गर्मियां बढ़ते ही घरों, कारखानों और अन्य स्थलों में आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है, क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट अथवा शार्ट सर्किट होने की वजह से हो रही हैं। गत दिवस दिल्ली के विवेक विहार में एक चार मंजिला इमारत के फ्लैट में एसी में ब्लास्ट होने से इतनी भयंकर आग लगी कि अन्य फ्लैट भी उसकी चपेट में आ गए और नौ लोगों की जान चली गई। इसके एक दिन पूर्व दिल्ली के ही जौहरीपुर में एसी में ब्लास्ट होने से एक बच्चे की जान चली गई थी। इसके और पहले दिल्ली के ही निकट इंदिरापुरम में एक बहुमंजिला इमारत में शार्ट सर्किट से आग भड़की। इस आग में लोगों की जान तो नहीं गई, लेकिन कई फ्लैट पूरी तरह से खाक हो गए। इस घटना में यह भी सामने आया कि गाजियाबाद का अग्निशमन विभाग ऐसे पर्याप्त उपकरणों से लैस नहीं था कि वह आग पर शीघ्र काबू पा पाता। ये घटनाएं तो केवल दिल्ली और उसके आसपास की हैं। ऐसी घटनाएं अन्य शहरों में भी सामने आ रही हैं और ज्यादातर के पीछे एसी अथवा किसी अन्य बिजली उपकरण में खामी-खराबी को रेखांकित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अपने यहां बिजली उपकरणों के निर्माण में गुणवत्ता संबंधी मानकों की अनदेखी हो रही है। ऐसा लगता है कि एसी के मामले में यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जो भी हो, उन नियम-कानूनों को सही तरह से अमल में लाने की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि बिजली उपकरणों का निर्माण निर्धारित गुणवत्ता के हिसाब से हो।अपने देश में बिजली समेत हर तरह के उपकरणों की गुणवत्ता के मानक तो बने हुए हैं, लेकिन आम तौर पर यह देखने में आता है कि ऐसे उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनियां उनकी अनदेखी ही करती हैं। दोयम दर्जे के उत्पादों का निर्माण उपभोक्ताओं के साथ किया जाने वाला छल ही है। कई बार तो यह छल जानलेवा साबित होता है। गुणवत्ताहीन उत्पादों का निर्माण कोई नई समस्या नहीं है। चूंकि इस समस्या का समाधान नहीं किया जा पा रहा है, इसलिए दोयम दर्जे के उत्पादों का बनना और बिकना जारी है। हालांकि प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि उद्यमियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तभी छाप छोड़ सकते हैं, जब उनके उत्पाद विश्वस्तरीय होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी बातों का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय मानक ब्यूरो को और अधिक सजगता एवं सक्रियता का परिचय देना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक लोगों को बिजली उपकरणों का उपयोग करने में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।

मजदूरों के असंतोष

नोएडा में कारखाना मजदूर सड़क पर उतरे। वहां की घटनाओं ने उन हालात की ओर ध्यान खींचा, जिससे हाल में देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूर आंदोलित हुए हैं। मजदूरों के असंतोष पर सहानुभूति से ध्यान दिया जाना चाहिए।उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर नोएडा में मजदूरों का उबलता असंतोष सोमवार को सड़कों पर छलक गया। हिंसा, आगजनी और पुलिस कार्रवाई ने वहां उन हालात की ओर ध्यान खींचा, जिस कारण हाल में देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूर आंदोलित हुए हैं। वैसे, तो इन आंदोलनों के स्थल देश भर में फैले हुए हैं, लेकिन खास चर्चा हरियाणा में हुई आंदोलनात्मक गतिविधियों की हुई। आखिरकार उनका असर हुआ, और हरियाणा सरकार ने आठ अप्रैल को सभी श्रेणियों के कर्मियों की न्यूनतम मजदूरी में 35 प्रतिशत बढ़ोतरी का एलान किया। इस निर्णय का असर नोएडा में देखा गया।कुछ ही दूरी पर एक जैसे काम के लिए अलग-अलग मजदूरी की बात उन्हें चुभी और वे भी आंदोलन पर उतर आए। वैसे भी एक विश्लेषण के मुताबिक 2016 से अब तक दिल्ली और हरियाणा की तुलना में उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी काफी कम बढ़ी है। दिल्ली में ये वृद्धि लगभग 90 फीसदी और हरियाणा में 89 प्रतिशत रही, जबकि उत्तर प्रदेश में इसमें महज 42.6 फीसदी का इजाफा हुआ है। यानी गुजरे एक दशक में हुई मुद्रास्फीति के अनुपात में यूपी में मजदूरी नहीं बढ़ी है। ऐसे में मजदूरों के असंतोष को समझा जा सकता है। इस बीच श्रम कानूनों की जगह श्रम संहिताएं लागू होने और आठ घंटे काम की सीमा हटाए जाने की वजह से मजदूर पहले मिली वैधानिक सुरक्षाओं से वंचित हो गए हैं।उनकी पीड़ा को एक मजदूर की एक टीवी चैनल पर कही गई इस बात से समझा जा सकता है कि रोजाना 12 घंटे काम करने के बाद उन्हें महीने में 13 हजार रुपये मिलते हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कारखाना मालिकों और मजदूरों के बीच संवाद कायम करने के लिए एक समिति बनाई है। मगर साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे नक्सलवाद को पुनर्जीवित करने की साजिश का शक भी जता दिया है। ऐसे में यह नहीं लगता कि मजदूर सरकार से किसी हमदर्दी की आशा कर सकते हैं। मगर ऐसे नजरियों से उस वक्त औद्योगिक शांति कायम करना कठिन होगा, जब श्रमिक वर्ग पर बढ़ते आर्थिक संकट की गहरी मार पड़ी है।

नागरिकों की समस्या बढ़ाते जटिल नियम

डॉ. ब्रजेश कुमार तिवारी

ओडिशा के क्योंझर जिले की घटना केवल एक विचलित कर देने वाली खबर नहीं, बल्कि यह भारतीय प्रशासनिक और बैंकिंग व्यवस्था का एक कुरूप चेहरा भी है। एक आदिवासी व्यक्ति अपनी मृत बहन के बैंक खाते से लगभग 19,300 रुपये निकालने के लिए इतना विवश हुआ कि वह उसका कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। बैंक की ओर से कहा गया कि मृत्यु प्रमाणपत्र और कानूनी उत्तराधिकारी से जुड़े दस्तावेज आवश्यक थे, जबकि परिजन का आरोप था कि उसे बार-बार लौटाया गया। हालांकि डिजिटल मीडिया पर आलोचना के बाद प्रशासन के हस्तक्षेप से उन्हें उनकी राशि दे दी गई, पर बात यहीं नहीं खत्म होती। यह घटना इसलिए अधिक पीड़ादायक है, क्योंकि भारत ने पिछले एक दशक में वित्तीय समावेशन की बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत करोड़ों बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं, ग्रामीण परिवारों और कमजोर वर्गों की है। इसका अर्थ है कि बैंकिंग अब केवल शहरों, वेतनभोगी वर्ग और शिक्षित लोगों की सुविधा नहीं रही, बल्कि गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, महिला और असंगठित क्षेत्र के नागरिक के जीवन से सीधे जुड़ गई है, लेकिन यही उपलब्धि अब हमें एक नए प्रश्न के सामने खड़ा करती है कि खाता खोलना तो आसान हो गया, पर खाते का अधिकार पाना क्या सचमुच आसान हुआ?

ओडिशा की घटना बताती है कि वित्तीय समावेशन का अगला चरण केवल बैंक खाता नहीं, बल्कि बैंकिंग न्याय होना चाहिए। हालांकि बैंकिंग नियमों का अपना महत्व है। मृत जमाकर्ता के खाते से पैसा किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। धोखाधड़ी रोकना, वास्तविक उत्तराधिकारी की पहचान बैंक को भविष्य के विवादों से बचाना आवश्यक है, लेकिन नियम का उद्देश्य न्याय होना चाहिए, नागरिक को अपमानित करना नहीं। नियम सुरक्षा दें, भय नहीं। प्रक्रिया मार्गदर्शन दे, भ्रम नहीं। आरबीआइ ने भी मृत जमाकर्ताओं के दावों के निपटान को सरल और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया है, लेकिन समस्या यह है कि नियमों की संवेदनशील व्याख्या शाखा स्तर तक नहीं पहुंचती। शहरों में बैंक कर्मचारी ग्राहक को फार्म, ईमेल, हेल्पलाइन और कस्टमर केयर से जोड़ देते हैं, लेकिन ग्रामीण भारत में बैंक शाखा ही नागरिक के लिए पूरा सिस्टम है। वहां शाखा प्रबंधक, बैंक मित्र, पंचायत सचिव, पटवारी, तहसीलदार और पुलिस, सभी मिलकर नागरिक के लिए 'राज्य' का चेहरा बन जाते हैं। यदि इस चेहरे पर संवेदना नहीं है, तो नागरिक के लिए लोकतंत्र कागजों का ढेर बन जाता है।आज भारत डिजिटल भुगतान, यूपीआइ, आधार और जन-धन के माध्यम से वित्तीय समावेशन की दुनिया में

उदाहरण बन चुका है, लेकिन सूचकांक और योजनाएं अपने-आप गरीब नागरिक की समस्या हल नहीं करतीं। असली परीक्षा तब होती है जब कोई अशिक्षित, आदिवासी, विधवा, बुजुर्ग या अकेला व्यक्ति बैंक के काउंटर पर खड़ा होता है और पूछता है कि अब मुझे क्या करना है? सिस्टम को बदलने की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। सबसे पहले, मृत खाताधारक के छोटे दावों के लिए एक सरल दावा प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए। यदि खाते में राशि एक लाख रुपये से कम हो, तो ग्राम पंचायत, स्थानीय राजस्व अधिकारी, आधार आधारित पहचान, परिवार रजिस्टर, मृत्यु की स्थानीय पुष्टि और दो गवाहों के आधार पर प्राथमिक दावा स्वीकार किया जाना चाहिए। बड़ी राशि के मामलों में ही विस्तृत जांच आवश्यक होनी चाहिए। हर बैंक शाखा में मृत दावा सहायता डेस्क या कम-से-कम एक प्रशिक्षित अधिकारी हो, जो परिजन को चरणबद्ध तरीके से बताए कि कौन-सा फार्म भरना है, मृत्यु प्रमाणपत्र कहां से बनेगा, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र की जरूरत कब है, नामिनी न होने की स्थिति में क्या करना है और दावा कितने दिन में निपटेगा? बैंक और स्थानीय प्रशासन के बीच एक फील्ड वेरिफिकेशन प्रोटोकाल भी होना चाहिए। यदि कोई गरीब, अशिक्षित या दूरस्थ क्षेत्र का नागरिक मृत खाताधारक का दावा लेकर आता है और दस्तावेज अधूरे हैं, तो बैंक उसे वापस न भेजे, बल्कि उसकी समस्या का समाधान करे। ग्रामीण भारत में सत्यापन केवल कागज से नहीं, समुदाय से भी होता है। सरपंच, वार्ड सदस्य, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, ग्राम रोजगार सेवक ये सभी स्थानीय वास्तविकता से परिचित होते हैं। सिस्टम यदि इन्हें जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ जोड़े, तो गरीबों को दफ्तर-दफ्तर नहीं भटकना पड़ेगा।इसके अलावा मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को आसान और समयबद्ध बनाया जाना चाहिए। नामिनी को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता अभियान का हिस्सा भी बनाया जाना चाहिए। आज करोड़ों बैंक खाते खुले हैं, लेकिन कितने खातों में नामिनी सही ढंग से दर्ज हैं, यह बड़ा प्रश्न है। अनक्लेम्ड डिपोजिट की समस्या को गंभीरता से लेना होगा। भारतीय बैंकों में हजारों करोड़ रुपये ऐसे खातों में पड़े हैं जिन पर किसी ने दावा नहीं किया है। लोगों का उत्तरदायित्व भी तय होना चाहिए। साथ ही सिंगल विंडो व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, तो परिवार को बैंक, बीमा, पेंशन, राशन, आधार, भूमि रिकार्ड और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अलग-अलग दफ्तरों में न जाना पड़े।

(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)

दूरगामी नुकसान करा बैठे दक्षिणी राज्य

ए. सूर्यप्रकाश

बीते दिनों कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल संसदीय परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधन की राह में अवरोध पैदा करने में सफल रहे। इस कवायद में कांग्रेस को दक्षिण भारतीय नेताओं का व्यापक रूप से सहयोग मिला। इस घटनाक्रम की गहन पड़ताल करें तो नेताओं का यह रुख दक्षिणी राज्यों के लिए ही भारी भूल साबित हो सकता है। यह विडंबना ही है कि कांग्रेस, द्रमुक और माकपा जैसे दल इस मुद्दे की गहराई और गंभीरता को समझने में विफल रहे और उन्होंने एक बेहतर अवसर गंवा दिया। प्रस्ताव के सकारात्मक पहलुओं से अधिक मोदी सरकार के प्रति नफरत और नकारात्मकता ही उनके इस निर्णय का मुख्य आधार रही।इस मुद्दे की गहराई में जाएं तो संविधान का अनुच्छेद 81 कहता है कि लोकसभा में प्रत्येक राज्य को सीटों की आवंटन प्रक्रिया में सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए हरसंभव रूप से व्यावहारिक एवं एकसमान हो। इसी क्रम में अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को लोकसभा सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 'ऐसी प्राधिकारी संस्था द्वारा और ऐसे तरीके से पुनर्गठित किया जाएगा जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे।' इस दृष्टि से सरकार और संसद के पास ही यह गुंजाइश है कि वे परिसीमन आयोग की 'व्यावहारिकता' पर विचार करने और केवल जनसंख्या के आंकड़ों पर ही कड़ाई से चलने के बजाय '50 प्रतिशत' से अधिक

वाली संकल्पना को आगे बढ़ाने का निर्देश दे सकें। सरकार द्वारा लोकसभा सीटों में 'एकमुश्त 50 प्रतिशत' की वृद्धि संबंधी आश्वासनों की गंभीरता का भी संज्ञान लिया जाना चाहिए था।वर्ष 1971 में परिसीमन न होने के बाद से ही लोकसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग जोर पकड़ती रही। वर्ष 2001 में वाजपेयी सरकार के दौरान भाजपा नेता मदनलाल खुराना ने भी मुखरता से ऐसी मांग सामने रखते हुए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 800 से अधिक करने की बात कही थी। हालांकि चंद्रबाबू नायडू, रामकृष्ण हेगड़े और करुणानिधि जैसे दक्षिण भारतीय नेताओं ने जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को लेकर आपत्ति जताई। उनका मानना था कि दक्षिणी राज्यों ने केंद्र सरकार की परिवार नियोजन नीतियों को कहीं बेहतर तरीके से लागू किया था, ऐसे में जनसंख्या के आधार पर होने वाला परिसीमन उन्हें नुकसान पहुंचाता। इसके चलते ही नायडू ने एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री वाजपेयी के पास भेजा और परिसीमन को रोकने की मांग की। वाजपेयी ने इस मांग को स्वीकार किया और अनुच्छेद 81 में संशोधन का निर्णय लिया। इससे लोकसभा की मौजूदा सीटों को 2026 की जनगणना तक स्थिर रखा गया।इस संदर्भ में दक्षिणी राज्यों की संवेदनाओं को समझते हुए मोदी सरकार ने अनुच्छेद 81 के प्रविधानों को दरकिनार कर परिसीमन संबंधी संवैधानिक संशोधन में एक प्रस्ताव रखा, जिसके तहत सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जानी थी। यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता तो दक्षिणी राज्यों के लिए लाभ की स्थिति बन सकती थी, लेकिन वहां के अधिकांश राजनीतिक दलों ने इसका अंधविरोध किया। तेलुगु देसम, जन सेना और वाइएसआर कांग्रेस जैसे दलों के समर्थन के बावजूद संविधान संशोधन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। दिलचस्प बात यही है कि यदि यह प्रस्ताव अमल में आता तो शायद उत्तरी राज्यों को जनसंख्या वृद्धि के बाद भी उसका अपेक्षित अनुपातिक लाभ नहीं मिलता। इसके बावजूद उनकी ओर से शिकायत सामने नहीं आई। चूंकि दक्षिणी राज्य इसका विरोध कर रहे थे, इसलिए शायद उन्हें यह महसूस हो रहा हो कि इसमें उनका कुछ फायदा ही हो।यदि जनसांख्यिकी परिदृश्य की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए देश की कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर 2.1 होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि एक औसत महिला को अपने जीवनकाल में 2.1 बच्चों को जन्म देना चाहिए। यदि टीएफआर 2.1 से नीचे आए तो जनसंख्या घटने लगती है। भारत में 1970 के दौर से ही उत्तर और मध्य भारत के राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों की टीएफआर में स्पष्ट रूप से गिरावट दर्ज हुई थी। वर्ष 2001 के आंकड़े देखें तो भारत की टीएफआर काफी अधिक (3.2) थी, जो 2011 में गिरकर 2.4 रह गई। अब इसके घटकर 2 होने का अनुमान है, जो जनसंख्या स्थिरता की कसौटी के पैमाने से भी कम है। यह निश्चित ही एक उल्लेखनीय सुधार है, क्योंकि ढाई दशक पहले जनसांख्यिकी विशेषज्ञ और नीति-निर्माता ऊंची टीएफआर को लेकर अत्यंत चिंतित थे।हालांकि इस उपलब्धि के बाद भी कुछ रुझान असंतुलन की ओर संकेत करते हैं। जैसे पिछले दो दशकों में दक्षिण भारतीय राज्यों की टीएफआर में भारी गिरावट आई है, जबकि उत्तर भारतीय राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) में यह दर ऊंची बनी हुई है। वर्ष 2021 में उत्तरी राज्यों के अनुमानित टीएफआर की बात करें तो यह बिहार में 3, मध्य प्रदेश में 2.6, राजस्थान में 2.4 और उत्तर प्रदेश में 2.7 संभव है। यानी इन राज्यों में अगले कुछ दशकों के दौरान जनसंख्या वृद्धि का रुझान बना रहेगा।जबकि दक्षिणी राज्यों मे केरल, तमिलनाडु और आंध्र का टीएफआर 1.5 तक गिर चुका है। कर्नाटक और तेलंगाना में यह 1.6 है। इस तरह देखा जाए तो केरल और तमिलनाडु में 2001 से ही टीएफआर 2.1 से नीचे पहुंच गया, जबकि बड़े उत्तरी राज्यों में यह करीब चार के दायरे में रहा। चूंकि जनगणना की प्रक्रिया आरंभ हो गई है, इसलिए परिसीमन अब अनुच्छेद 81 और 82 के प्रविधानों के अनुरूप ही होगा।इसमें जनसंख्या की कसौटी ही मुख्य आधार बनेगी तो उत्तरी राज्यों की सीटों में उससे भी अधिक बढ़ोतरी होगी जो फार्मूला अभी केंद्र सरकार सुझा रही था। स्वाभाविक है कि दक्षिणी राज्यों को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे वे चाहते तो बच सकते थे। प्रतीत होता है कि तात्कालिक राजनीतिक लाभ के फेर में वे दूरगामी नुकसान करा बैठे हैं।

(लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ ?एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

प0 बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या देश की राजनीत तय करेंगे

अजय दीक्षित

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो भी परिणाम आएंगे वे देश के 2029 लोकसभा चुनाव की दिशा ब दशा तय करेंगे। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम चार मई को आयेंगे। इन चुनावों में मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तुड़मूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस भी मैदान में है। ममता बनर्जी की तुड़मूल कांग्रेस 2011से सत्ता में है जबकि भारतीय जनता पार्टी 2021 के विधानसभा चुनाव में 40 फीसदी वोट लाकर 294 सदस्यीय विधानसभा में 77 सीट जीती थी। लेकिन ममता बनर्जी की तुड़मूल कांग्रेस ने 48 फीसदी वोट ले कर 213 सीट जीती थी।भारतीय जनता पार्टी का सपना रहा है कि वह अंग,बंग, और कलिंग में सरकार बनाए। उसके अंग (बिहार) कलिंग (ओडिशा) में सरकार बन गई है और अब बंग (बंगाल) की बारी है । जनसंघ यानि आज की भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के ही थे। स्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई कहते थे कि बंगाल जितने का सपना एक दिन पूरा होगा । लालकृष्ण आडवाणी, सुंदर सिंह भंडारी, दीन दयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेई , कृष्णलाल शर्मा ने एक सेमिनार में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि पश्चिमी बंगाल में सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि वह पैन इंडिया पार्टी बने जिसका समूचे देश में सत्ता हो । ऐसा लगता है कि भाजपा ने,80 फीसदी लक्ष पूरा कर लिया है।आज उसकी संपूर्ण हिंदी भाषा के राज्यों , पूर्वोत्तर राज्यों, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा,में सरकार है।जबकि दक्षिण भारत में कर्नाटक में सरकार रह चुकी है।केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राज्य शेष है। तेलंगाना में विरोधी दल है। अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुमत लाती है तो वह 2029 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर आसानी बहुमत प्राप्त कर लेगी । क्योंकि अभी 240 जीत गई थी क्योंकि महाराष्ट्र,उत्तर, प्रदेश,बंगाल लगभग 100 सीट बढ़ा लेगी जो अकड़ा 340 सीट का होगा इसमें जेडीयू,शिवसेना, एनसीपी,का योग अलग होगा । ,उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।दूसरा सवाल यह है कि अगर तुड़मूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतती है तो ममता बनर्जी राष्ट्रीय क्षितिज पर भारतीय राजनीत में 2029 लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एक जुट कर अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पेश कर सकती है।इस घटना क्रम के बाद समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों, बीजेडी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस,आप, ममता बनर्जी को नेता घोषित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पेश कर सकती है।यद्यपि कांग्रेस भी चाहेगी ये सभी पार्टियों उनके झंडे तले चुनाव लड़े और चुनाव तक ममता बनर्जी को भी इस इंडी गठबंधन में लिया जाय लेकिन कांग्रेस प्रधानमंत्री पद से कम पर तैयार नहीं होगी। पाश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को कई मुद्दों पर घेरा है।यहां तक कि राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गुंडों की संज्ञा दी जो जनता से अवैध उगाही,कट मनी मांगते हैं। ममता बनर्जी पर उन्होंने मुस्लिम ध्रुवीकरण का आरोप भी लगाया।विपक्ष की एकता का रास्ता उत्तर प्रदेश, बिहार,से निकलेगा क्योंकि सपा नेता अखिलेश यादव, राजेडी के तेजस्वी यादव बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर उत्सुक हैं और ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं। बीजेडी के नेता नवीन पटनायक, दक्षिण में एम के स्टालिन,भी ममता बनर्जी के साथ है। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में सपा, कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव मैदान में आ सकते हैं। दूसरी ओर बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश की तैयारी भी शुरू करदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से बिगुल फूंकना चाहते हैं और हरदोई में594 किलो मीटर सिक्स लेन गंगा एक्सप्रेस वे का लोकार्पण भी दो दिन पहले किया है। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव मोड में आ गई है। मप्र, राजस्थान, दिल्ली,के कार्यकर्ताओं को समानांतर जिम्मेदारी दी जाएगी।राष्ट्रीय महासचिव बाल संतोष लखनऊ में है। लेकिन सपा भी तैयार है क्योंकि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में होना है।देश में उत्तर प्रदेश में 80, जम्मू कश्मीर 06, हिमाचल प्रदेश 04, उत्तराखंड 05,दिल्ली 07, गुजरात 26, राजस्थान 25, मध्य प्रदेश 29, छत्तीसगढ़ 011, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42 ओडिशा 21, झारखंड 11,बिहार 40, असम 14, तेलंगाना 17, आंध्र प्रदेश 23, तमिलनाडु 39,केरल 20, कर्नाटक 28, त्रिपुरा 2,गोवा 02, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल कुल 10 सीट है।कुलमिलाकर 542 ।पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है जो देश की आगामी राजनीति की दिशा ब दशा तय करेंगे।

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में पीएलआई योजना का परिवर्तनकारी प्रभाव

श्रीअविनाश जोशी

भारत आज अपने आर्थिक सफर के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अब जबकि हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में अग्रसर है, विकास को सिर्फ उत्पादन की मात्रा से ही नहीं, बल्कि हमारे द्वारा सृजित मूल्य के आधार पर भी मापना होगा।खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की तुलना में बहुत कम क्षेत्र ही ऐसे हैं, जहां इस प्रकार का बदलाव बिल्कुल साफ नजर आता है।भारत खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों, दूध और समुद्री उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। दशकों तक, हमारे कृषि संबंधी सामर्थ्य ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। फिर भी, इस उपज का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक रूप से बेहद ही सीमित मूल्यवर्धन के साथ सीधे खेत से बाजार तक पहुंचता रहा।

आज भारत के कृषि उत्पादन का महज 12-13 प्रतिशत हिस्सा ही प्रसंस्करण से गुजरता है। उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच का यही अंतर भारतीय अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सबसे बड़े अवसरों में से एक है। इसलिए, खाद्यान्नों से जुड़ी भारत की यात्रा का अगला चरण बिल्कुल स्पष्ट हैः कृषि की प्रचुर संपदा को उच्च मूल्य वाले एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खाद्य उत्पादों में परिवर्तित करना।

पीएलआई योजना के पीछे की परिकल्पना

इस अवसर को पहचानते हुए, भारत सरकार ने मार्च 2021 में कुल 10,900 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) की शुरुआत की।खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा इस योजना को 2021-22 से 2026-27 तक की छह साल की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। इस योजना के पीछे का मूल विचार सरल लेकिन ठोस हैः खाद्य प्रसंस्करण क्षमता, नवाचार और वैश्विक ब्रांडिंग के विस्तार में निवेश करने वाली कंपनियों को पुरस्कृत करना। कुल मिलाकर, यह योजना इन-स्टोर ब्रांडिंग, अंतरराष्ट्रीय खुदरा श्रृंखलाओं में शेल्फ स्पेस और वैश्विक विपणन अभियानों में निवेश करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके भारत में खाद्य उत्पादन से जुड़ी वैश्विक स्तर की कई चैंपियन कंपनियां तैयार करती है।

रणनीतिक डिजाइनः एक आधुनिक खाद्य इकोसिस्टम

का निर्माण

पीएलआईएसएफपीआई योजना की संरचना को सावधानीपूर्वक को तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित रखा गया है।

1. उच्च क्षमता वाले खाद्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना

पहला घटक पकाने के लिए तैयार (रेडी-टू-कुक) और खाने के लिए तैयार (रेडी-टू-ईट) खाद्य पदार्थ, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद जैसी प्रमुख खाद्य श्रेणियों में उत्पादन बढ़ाने पर केन्द्रित है।ये श्रेणियां वैसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत घरेलू खपत और निर्यात क्षमता, दोनों में तेजी से विस्तार कर सकता है।

1. नवाचार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भागीदारी को प्रोत्साहन देना

दूसरा घटक एमएसएमई द्वारा विकसित नवोन्मेषी और जैविक खाद्य उत्पादों को समर्थन प्रदान करता है। लघु एवं मध्यम उद्यम भारत के खाद्य क्षेत्र की रीढ़ हैं और समावेशी विकास हेतु आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ उनका जुड़ाव बेहद जरूरी है।

पोषक अनाज (मिलेट) से संबंधित नवाचारः परंपरा को आधुनिक बाजारों से जोड़ना

वर्ष 2023 में, अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज (मिलेट्स) वर्ष के उपलक्ष्य में, मंत्रालय ने पीएलआई योजना के तहत एक विशेष पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य पकाने के लिए तैयार (रेडी-टू-कुक) और खाने के लिए तैयार (रेडी-टू-ईट) उत्पादों में मिलेट्स के उपयोग को प्रोत्साहित करना था।

मिलेट्स जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी, अत्यधिक पौष्टिक और भारत की कृषि परंपराओं में गहराई से जुड़े हुए हैं।आधुनिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मिलेट्स का समावेश करके, यह योजना पोषण संबंधी सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी कृषि को एक साथ बढ़ावा देती है।

बदलाव से जुड़े आंकड़े

पीएलआई योजना के तहत बहुत ही कम समय में हासिल की गई प्रगति उद्योग जगत की ओर मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया और इस नीति की प्रभावशीलता को दर्शाती है। अब तकः इस योजना के तहत 165 कंपनियों को मंजूरी दी गई है।

इनमें से 68 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं, साथ ही बड़ी कंपनियों के 40 संविदा निर्माता भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 9,207 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। प्रति वर्ष लगभग 35 लाख मीट्रिक टन की नई प्रसंस्करण और संरक्षण संबंधी क्षमता सृजित की गई है। इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3.29 लाख रोजगार सृजित हुए हैं।ध्यान रखने लायक बात यह है कि इस योजना का मूल लक्ष्य 25 लाख रोजगार सृजित करना था। इस क्षेत्र ने पहले ही इस लक्ष्य का 131 प्रतिशत हिस्सा हासिल कर लिया है।पीएलआई समर्थित कंपनियों द्वारा प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की बिक्री में भी 2019-20 से 13.23 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है।

(निर्यात में वृद्धि दर 2019-20 से 7.41 प्रतिशत की है)

विभिन्न पीएलआई योजनाओं के बीच एक चमकता सितारा

उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के 14 क्षेत्रों को कवर करती है। इनमें से, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित पीएलआई सबसे प्रभावशाली योजनाओं में से एक बनकर उभरी है।कुल पीएलआई सब्सिडी वितरण में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का हिस्सा मात्र 8 से 9 प्रतिशत ही होने के बावजूद, इसने तमाम पीएलआई योजनाओं के तहत सृजित किए गए कुल रोजगारों में से लगभग 42 प्रतिशत रोजगार सृजित किए हैं।अब तक, इस योजना के तहत कुल 2715 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की जा चुकी है। यह कुल परिव्यय का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा है।यह साबित करता है कि खाद्य प्रसंस्करण भारत के मैन्यूफैक्चरिंग इकोसिस्टम में सबसे अधिक रोजगार सृजित करने वाले क्षेत्रों में से एक है।

उपभोक्ताओं की बदलती जीवनशैली के अनुरूप बदलाव

भारत के जनसांख्यिकीय परिवर्तन का असर खाद्य उद्योग पर भी पड़ रहा है।

युवा और शहरीकरण की ओर अग्रसर आबादी की बढ़ती मांगें इस प्रकार हैंः खाद्य संबंधी सुविधाजनक उपाय

स्वच्छ पैकेजिंग

सुरक्षित और पौष्टिक खाने के लिए तैयार (रेडी-टू-ईट) उत्पाद बेंगलुरु, मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में काम करने वाले पेशेवर अक्सर पकाने के लिए तैयार (रेडी-टू-कुक) या खाने के लिए तैयार (रेडी-टू-ईट) वैसे गुणवत्तापूर्ण भोजन की तलाश में रहते हैं जो उनकी तेज रफ्तार जीवनशैली के अनुरूप हो। भारत की प्रचुर कृषि संपदा इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे सामने इस प्रचुर संपदा को सतत आर्थिक मूल्य में बदलने की चुनौती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना इस बदलाव को गति देने में सहायक साबित हो रही है और खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर खाद्यानों के मामले में नेतृत्व का सपना शीघ्र ही साकार होने वाला है।

लेखक आईएएस अधिकारी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव हैं।

किसानों को बढ़ी क्षतिपूर्ति, टेक्सटाइल पार्क, फेलोशिप और ई-गवर्नेंस से विकास को रफ्तार

लखनऊ (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार और विकास को गति देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आगे बढ़ाया है। ऊर्जा, शिक्षा, न्यायिक व्यवस्था, पर्यावरण, उद्योग और प्रशासनिक सुधार से जुड़े इन निर्णयों का सीधा लाभ आम जनता, किसानों, युवाओं और कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है।ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए पावर ट्रांसमिशन परियोजनाओं में किसानों और भूस्वामियों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप करने का प्रस्ताव है। अब टावर बेस क्षेत्र के लिए 200 प्रतिशत तक मुआवजा दिया जाएगा, जबकि राइट ऑफ वे कॉरिडोर के 30 प्रतिशत क्षेत्रफल के लिए भी भूमि लागत के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इससे पारेषण लाइनों से प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी।न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ खंडपीठ में कार्यरत लॉ क्लर्क (ट्रेनी) और रिसर्च एसोसिएट का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर अधिकतम 3 वर्ष करने का प्रस्ताव है। इससे न्यायमूर्तियों को विधिक शोध कार्य में अधिक दक्ष सहयोग मिल सकेगा और मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के तहत संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना के अंतर्गत 10 टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स की 4 बंद पड़ी मिलों की 251.805 एकड़ भूमि को हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है।शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में नेल्को नेटवर्क प्रोडक्ट लिमिटेड (टाटा एंटरप्राइजेज) के सहयोग से प्रदेश के 150 राजकीय विद्यालयों में उेंर्ड स्किल लैब स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन लैब्स के माध्यम से छात्रों को रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जोड़ते हुए रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाएगा।जल आपूर्ति से जुड़े एक अहम निर्णय में झांसी बबीना पेयजल योजना के तहत 17.65 करोड़ रुपये की बकाया राशि उ.प्र. जल निगम (नगरीय) को देने का प्रस्ताव है। यह धनराशि पंचायती राज विभाग के माध्यम से राज्य वित्त आयोग की निधि से समायोजित की जाएगी, जिससे संबंधित कर्मचारियों और पेंशनरों के भुगतान सुनिश्चित हो सकेंगे।सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए स्थानांतरण नीति भी लागू की है, जिसके तहत 31 मई तक तबादले किए जाएंगे। निर्धारित अवधि पूरी कर चुके अधिकारियों का स्थानांतरण अनिवार्य होगा और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम अपनाया जाएगा।उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फिरोजाबाद में अमरदीप विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने का प्रस्ताव है, जिससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार होगा।प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत 'ऊ0-एफ फेलोशिप' कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में दो विशेषज्ञ फेलो तैनात किए जाएंगे, जो विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग और डेटा विश्लेषण में सहयोग करेंगे। चयनित फेलो को 50 हजार रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक सहित अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाने के लिए ई-साक्ष्य प्रबंधन नियम 2026, ई-समन व्यवस्था और सामुदायिक सेवा गाइडलाइंस लागू करने का प्रस्ताव है। इससे डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन, ऑनलाइन समन और छोटे अपराधों में सुधारात्मक दंड की व्यवस्था मजबूत होगी।पर्यावरण संरक्षण के तहत वर्ष 2026-27 में 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। वन विभाग द्वारा 50 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे और विभिन्न विभागों, संस्थाओं व आम नागरिकों को निःशुल्क पौधे वितरित किए जाएंगे, जिससे जनसहभागिता के साथ हरित अभियान को गति मिलेगी।सरकार के इन फैसलों को व्यापक विकास, पारदर्शिता और जनकल्याण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, जिससे प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

जनता दर्शन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सुनीं सैकड़ों फरियाद, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

लखनऊ (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अपने कैंप कार्यालय 7-कालिदास मार्ग पर आयोजित 'जनता दर्शन' कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित, प्रभावी व न्यायसंगत समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने एक-एक फरियादी की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मामलों का समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।जनता दर्शन में भूमि विवाद, राजस्व से जुड़े मामले, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, बिजली-पानी, पुलिस कार्रवाई, शिक्षा और रोजगार

से संबंधित समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम आमजन से सीधे जुड़ने का प्रभावी माध्यम है, जिससे जमीनी हकीकत सामने आती है और शासन-प्रशासन को वास्तविक समस्याओं का आकलन करने में मदद मिलती है।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां आवश्यकता हो, वहां मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाए और पीड़ितों को तत्काल राहत दी जाए। विशेष रूप से भूमि विवाद और अवैध कब्जे से जुड़े मामलों में उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर भेजी जाए और प्रभावी कार्रवाई कर समाधान कराया जाए।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी जरूरतमंद वंचित न रहे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनहित सर्वोपरि है और सरकार आम जनता की भलाई के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।कार्यक्रम के दौरान मौर्य ने फरियादियों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का हर संभव समाधान किया जाएगा और किसी को भी निराश नहीं लौटने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का निस्तारण इस प्रकार किया जाए कि पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट हो और उसे बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।महिलाओं, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों में विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने दोहराया कि प्रत्येक शिकायत की जवाबदेही तय की जाए और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को राहत मिल सके।

बंगाल, असम व पुडुचेरी में भाजपा की जीत पर प्रदेश नेतृत्व उत्साहित, 'मिशन 2027' को मिलेगी नई ऊर्जा

लखनऊ (यूएनएस)। पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली सफलता पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने बधाई देते हुए इसे विकास और सुशासन की राजनीति की जीत बताया है।प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को इस सफलता का प्रमुख आधार बताते हुए कहा कि यह परिणाम देश में विश्वास, पारदर्शिता और विकास आधारित राजनीति की स्वीकार्यता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि गंगोत्री से गंगासागर तक भाजपा को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है और बंगाल में भय की राजनीति पर भरोसे की जीत हुई है।उन्होंने कहा कि असम में विकास की हैट्रिक यह साबित करती है कि जनता अब प्रदर्शन आधारित राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। पूर्वी भारत से उठी यह राजनीतिक लहर उत्तर प्रदेश के 'मिशन 2027' को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं और डबल इंजन सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।पंकज चौधरी ने बताया कि संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रदेश का दौरा किया जा रहा है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का उत्साह बेहद सकारात्मक है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी समय में भाजपा और अधिक मजबूती के साथ जनता के बीच कार्य करेगी और 2027 में सुशासन की हैट्रिक हासिल करेगी।प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने भी इन चुनावी परिणामों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत राष्ट्रवाद और विकास के प्रति जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा ने देशभर में जनसेवा और पारदर्शी शासन का जो मॉडल प्रस्तुत किया है, उसी के आधार पर जनता ने एक बार फिर पार्टी पर भरोसा जताया है।

बंगाल चुनाव रुझानों पर लखनऊ में भाजपा का जश्न, प्रदेश कार्यालय में ढोल-नगाड़ों पर थिरके कार्यकर्ता

लखनऊ (यूएनएस)। पश्चिम बंगाल चुनाव के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़त की खबरों के बीच राजधानी लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर नृत्य कर खुशी का इजहार किया और एक-दूसरे को बधाई दी।प्रदेश कार्यालय परिसर में उत्साह चरम पर रहा। महिला कार्यकर्ताओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और ढोल-नगाड़ों पर जमकर नृत्य किया। इस दौरान आतिशबाजी कर जीत के रुझानों का स्वागत किया गया, जिससे पूरा क्षेत्र उत्सव के रंग में नजर आया।जश्न में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ पारंपरिक बंगाली व्यंजन 'झालमुड़ी' का स्वाद लिया और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 'जय भाजपा' और 'मोदी है तो मुमकिन है' जैसे नारे लगाए।कार्यक्रम में एक युवक 'बुलडोजर मॉडल' लेकर पहुंचा, जिस पर '27 में फिर बुलडोजर' लिखा हुआ था। यह मॉडल कार्यकर्ताओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा और लोगों ने इसके साथ तस्वीरें भी

खिंचवाईं। कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन के रणनीतिकार सुनील बंसल की रणनीति का परिणाम ही है कि पार्टी को बंगाल में मजबूती मिल रही है।प्रदेश कार्यालय में देर तक जश्न का सिलसिला जारी रहा। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और सभी ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी।

प्रदेश में स्थानांतरण नीति 2026-27 लागू, 31 मई तक होंगे तबादले; अवधि पूरी करने वाले अधिकारियों का स्थानांतरण अनिवार्य

लखनऊ (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए नई स्थानांतरण नीति जारी कर दी है, जिसके तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 31 मई 2026 तक किए जाएंगे। नीति में पारदर्शिता, संतुलन और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।नई नीति के अनुसार समूह 'क' और समूह 'ख' के वे अधिकारी, जो किसी एक जनपद में 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं, उनका स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। वहीं, जो अधिकारी किसी एक मंडल में 7 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें भी उस मंडल से स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि विभागाध्यक्ष और मंडलीय कार्यालयों में तैनाती की अवधि को इस गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। मंडलीय कार्यालयों में अधिकतम तैनाती अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है और यहां लंबे समय से तैनात अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा।स्थानांतरण की सीमा भी तय की गई है। समूह 'क' और 'ख' के अधिकतम 20 प्रतिशत अधिकारियों का ही तबादला किया जा सकेगा, जबकि समूह

'ग' और 'घ' के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है। समूह 'ख' और 'ग' के कार्मिकों के स्थानांतरण यथासंभव मेरिट आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के जरिए किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।सरकार ने विशेष परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा है। दिव्यांग या पूर्ण रूप से चलन क्रिया से प्रभावित बच्चों के माता-पिता को उनकी सुविधा के अनुसार ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाएगा, जहां बच्चों के इलाज और देखभाल की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध हो।इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्रदेश के 8 जनपदों और 34 जनपदों के 100 आकांक्षी विकास खंडों में कर्मचारियों की तैनाती को प्राथमिकता देते हुए संतृप्तीकरण की व्यवस्था की गई है, ताकि इन क्षेत्रों का समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सके।नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण सत्र समाप्त होने के बाद समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों के तबादले विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ही किए जा सकेंगे।सरकार की इस नई स्थानांतरण नीति का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाना, कर्मचारियों के बीच संतुलन बनाए रखना और जनसेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।

ऐतिहासिक, धार्मिक विरासत का कायाकल्प करके आमजनमानस को समर्पित करना है-जयवीर

लखनऊ (यूएनएस)। पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के अंतर्गत गोरखपुर मंडल के महाराजगंज के लिए पर्यटन विकास की 9 परियोजनाओं के लिए 686 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार एवं बुनियादी सुविधाएं सुलभ कराने का कार्य किया जाएगा। विगत 9 वर्षों में महराजगंज का अवस्थापना सुविधाओं एवं धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के चलते भारी बदलाव आया है। कानून व्यवस्था बेहतर होने के साथ कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी हुई है। इससे पर्यटकों का आगमन बढ़ा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि महराजगंज के सिसवा मनिपरगढ़ मंदिर रूद्धरौली निचकौट के पर्यटन विकास के लिए 99 लाख रूपये, पनियरा,विकास खण्ड परतावल में राम जानकी मंदिर के लिए 54 लाख रूपये, नौतनवां सोनौली स्थित देवस्थान चांचाई माता मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 1 करोड़ रूपये, सदर जनपद महराजगंज में बेलहिया प्राचीन पीठ श्रीराम जानकी मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 87लाख रूपये, फरेन्दा विस के अंतर्गत स्थित दुर्गा मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 70 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

सैरपुर में बंद कमरे से युवक का सड़ा-गला शव बरामद, 2-3 दिन पहले फंदे पर लटककर मौत की आशंका

लखनऊ (यूएनएस)। राजधानी के थाना सैरपुर क्षेत्र स्थित न्यू कॉलोनी तरहिया में उस समय सनसनी फैल गई, जब कई दिनों से बंद पड़े एक कमरे से तेज दुर्गंध आने पर एक युवक का शव बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो युवक का शव छत के पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका मिला। प्रारंभिक जांच में घटना 2 से 3 दिन पुरानी प्रतीत हो रही है।पुलिस के अनुसार दिनांक 03 मई 2026 को सायंकाल करीब 07:30 बजे निशा निवासी न्यू कॉलोनी तरहिया थाना सैरपुर ने थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बताया कि वह 25 अप्रैल 2026 को अपने पुत्र राजू (उम्र लगभग 26 वर्ष) और पुत्री के साथ रिश्तेदारी में गई थीं। अगले दिन 26 अप्रैल को उनका पुत्र अकेले घर वापस आ गया था और घर पर अकेला रह रहा था। निशा ने बताया कि 26 अप्रैल की शाम को उनकी अपने पुत्र से मोबाइल फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद भी संपर्क बना रहा और अंतिम बार 30 अप्रैल 2026 को उनकी बेटे से फोन पर बात हुई थी। इसके बाद अचानक संपर्क बंद हो गया। जब वह 03 मई को अपनी पुत्री के साथ घर लौटीं तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज लगाने और दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसी दौरान कमरे के भीतर से तेज दुर्गंध आने लगी, जिससे अनहोनी की आशंका प्रबल हो गई।घटना की सूचना तत्काल थाना सैरपुर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिजनों व स्थानीय लोगों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया गया। अंदर का दृश्य देख सभी सन्न रह गए। युवक राजू का शव छत के पंखे से दुपट्टे का फंदा बनाकर लटका हुआ था।पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल को सुरक्षित कराया और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण करते हुए आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। मौके पर शव से तेज दुर्गंध आ रही थी और वह विघटित अवस्था में पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि घटना को 2 से 3 दिन का समय बीत चुका है।पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया और पंचायतनामा की कार्यवाही पूरी करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी।परिजनों के मुताबिक मृतक अविवाहित था और पानी-बताशे का ठेला लगाकर अपना जीवनयापन करता था। आसपास के लोगों के अनुसार वह शांत स्वभाव का युवक था। घटना के बाद इलाके में शोक और दहशत का माहौल है।

बीबीएयू में टेडएक्स कार्यक्रमः विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका पर जोर

लखनऊ (यूएनएस)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में सोमवार 4 मई को टेडएक्स कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, नवाचार, समावेशी विकास और युवाओं की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिशिर दीक्षित और डॉ. विजेंद्र चौहान उपस्थित रहे। इसके अलावा टेडएक्स मेंटर प्रो. संजय कुमार द्विवेदी, प्रो. सार्तिक बाघ, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूजन की निदेशक प्रो. जया श्रीवास्तव और फैकल्टी कोऑर्डिनेटर डॉ. पारिस्मिता मोहंती भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और बाबासाहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया।आयोजन समिति की ओर से कुलपति प्रो. मित्तल को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए प्रो. संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि टेडएक्स जैसे मंच युवाओं को अपने विचार साझा करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं।अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रो. राज कुमार मित्तल ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की केंद्रीय भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए स्वदेशी सोच, वोकल फॉर लोकल, टेक्नो नेशनलिज्म और आर्थिक राष्ट्रवाद को अपनाना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के लिए युवाओं

को नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार सृजक बनना होगा।उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा समाज में असमानताओं को दूर करने का सबसे प्रभावी माध्यम है और महिलाओं की भागीदारी के बिना समावेशी विकास संभव नहीं है। पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने नवाचार और शोध पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। साथ ही भारत की ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि देश को पुनः वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने के लिए संतुलित और मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण आवश्यक है।प्रो. जया श्रीवास्तव ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को विकास का आधार बताते हुए कहा कि सुरक्षित वातावरण मिलने पर महिलाएं समाज और अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी योगदान दे सकती हैं। उन्होंने महिलाओं को नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने प्रेरणादायक व्याख्यान प्रस्तुत किए, जिससे कार्यक्रम बौद्धिक रूप से समृद्ध हुआ। वहीं, नृत्य, गायन, लोकनृत्य और जादू शो जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में उत्साह और जीवंतता का संचार किया।

जर्जर दीवार गिरने से युवक की मौत, मिस्त्री चोटिल

लखनऊ (यूएनएस)। राजधानी के मड़ियांव इलाके में सोमवार सुबह जर्जर दीवार गिरने से 34 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा भरत नगर स्थित नॉज पैलेस के सामने हुआ। युवक कार का पहिया खोलकर पंक्चर बनवा रहा था, तभी पास की पुरानी ईंट की दीवार भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची मड़ियांव पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बाहर निकालकर केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अंकित शर्मा निवासी अतरौली, हरदोई के रूप में हुई है। वह भरत नगर में ग्रीन वैली मटर विक्रेता की दुकान पर काम करता था और वहीं रहता था। पुलिस के मुताबिक, सुबह तेज आंधी और बारिश के बाद अंकित अपने दुकान मालिक की कार का पंक्चर बनवाने के लिए एक मिस्त्री को बुलाकर पहिया खोल रहा था। इसी दौरान पास की जर्जर दीवार अचानक ढह गई।

न्यूज डायरी

मेदांता अस्पताल में अजय राय से मिले प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की दुआ

लखनऊ।(यूएनएस) राजधानी के मेदांता अस्पताल में सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय से प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुलाकात कर उनका कुशल-क्षेम जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की दुआ की। इस दौरान मुलाकात का माहौल सौहार्दपूर्ण रहा और गंगा-जमुनी तहजीब की झलक देखने को मिली।मुलाकात करने वालों में शाही इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, शिया मरकज़ी चांद कमेटी के अध्यक्ष और प्रमुख शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास नकवी तथा ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास शामिल रहे। सभी ने अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री मुईद अहमद, निवर्तमान प्रदेश महासचिव मुकेश सिंह चौहान और अरशद आज़मी भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।मुलाकात के दौरान अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रेम, भाईचारे और समावेशी राजनीति की पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि समाज के सम्मानित स्तंभों का समर्थन पार्टी के संघर्ष को नई ऊर्जा देता है और प्रबुद्धजनों का यह अपनत्व कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती प्रदान करता है।अजय राय ने आगे कहा कि यह मुलाकात गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की उस अटूट परंपरा का प्रतीक है, जिसे सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस हमेशा प्रतिबद्ध रही है।

मड़ियांव में जर्जर दीवार बनी मौत का कारण, वाहन का पहिया खोलते समय युवक दबकर मौत

लखनऊ (यूएनएस)। थाना मड़ियांव क्षेत्र के भरत नगर में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में जर्जर दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब युवक अपने मालिक की गाड़ी का पंचर बनवाने के दौरान पहिया खोल रहा था। अचानक पास की ईंट की दीवार भरभराकर गिर गई और युवक उसके नीचे दब गया।पुलिस के अनुसार दिनांक 04 मई 2026 को सुबह करीब 11:30 बजे थाना मड़ियांव पुलिस को सूचना मिली कि भरत नगर क्षेत्र में एक जर्जर दीवार गिरने से एक व्यक्ति दब गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे युवक को बाहर निकाला गया।घायल युवक को गंभीर अवस्था में तत्काल केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया जानकारी में मृतक की पहचान अंकित शर्मा (उम्र लगभग 34 वर्ष) पुत्र संतोष कुमार, मूल निवासी थाना अतरौली जनपद हरदोई के रूप में हुई है।पुलिस के मुताबिक अंकित शर्मा वर्तमान में भरत नगर स्थित ग्रीन वैली मटर के एक विक्रेता की दुकान पर कार्य करता था और वहीं रहता था। बताया जा रहा है कि सुबह हुई आंधी और बारिश के बाद वह अपने दुकान मालिक की कार पहिया गाड़ी, जो नॉज पैलेस नामक मकान के सामने सड़क पर खड़ी थी, का पंचर बनवाने के लिए एक मिस्त्री को लेकर पहुंचा था। इसी दौरान वह गाड़ी का पहिया खोल रहा था कि पास में स्थित जर्जर दीवार अचानक गिर गई।हादसे में साथ मौजूद पंचर बनाने वाला मिस्त्री मामूली रूप से घायल हुआ, जो घटना के बाद वहां से चला गया। उसका नाम और पता अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है।परिजनों के अनुसार मृतक विवाहित था और उसके दो छोटे बच्चे हैं।

अलग-अलग स्थानों पर दीवार ढहने से 2 युवक की मौत, दो घायल

लखनऊ (यूएनएस)। राजधानी लखनऊ में आंधी-पानी के बाद अलग-अलग स्थानों पर दीवार ढहने से 2 युवकों की मौत हो गई। 2 युवक घायल हो गए। एक घटना मड़ियांव और दूसरी विभूति खंड में हुई। दोनों मृतकों के शव को पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ के मड़ियांव इलाके में सोमवार सुबह जर्जर दीवार गिरने से 34 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा भरत नगर स्थित नॉज पैलेस के सामने हुआ। युवक कार का पहिया खोलकर पंक्चर बनवा रहा था, तभी पास की पुरानी ईंट की दीवार भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची मड़ियांव पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बाहर निकालकर केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अंकित शर्मा निवासी अतरौली, हरदोई के रूप में हुई है। वह भरत नगर में ग्रीन वैली मटर विक्रेता की दुकान पर काम करता था और वहीं रहता था। पुलिस के मुताबिक, सुबह तेज आंधी और बारिश के बाद अंकित अपने दुकान मालिक की कार का पंक्चर बनवाने के लिए एक मिस्त्री को बुलाकर पहिया खोल रहा था। इसी दौरान पास की जर्जर दीवार अचानक ढह गई। हादसे में पंक्चर मिस्त्री को मामूली चोट आई, जो बाद में वहां से चला गया। परिजनों ने बताया कि अंकित विवाहित था और उसके दो बच्चे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। विभूति खंड में हुंडई का सर्विस सेंटर है। उसके पास में सगे भाई अमित यादव और अमरीश यादव चाय-समोसे की दुकान चलाते थे। सोमवार सुबह दोनों भाई दुकान पर थे।

काशी विश्वनाथ मंदिर में रकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

लखनऊ (यूएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में धार्मिक पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या है। मार्च में करीब 65 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह न केवल प्रदेश में बढ़ती आस्था का प्रतीक है, बल्कि सरकार द्वारा विकसित की गई बेहतर व्यवस्थाओं का भी प्रमाण है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण के बाद मंदिर परिसर का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। पूर्ववर्ती सरकारों में जहां श्रद्धालुओं को संकरी गलियों और भीड़भाड़ का सामना करना पड़ता था, वहीं योगी सरकार में विशाल, भव्य और सुव्यवस्थित परिसर ने दर्शन को सहज और सुगम बना दिया है।काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के कारण मंदिर तक पहुंच आसान हुई है, देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। योगी सरकार ने मंदिर परिसर में साफ-सफाई, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी है। आधुनिक शौचालय, पेयजल व्यवस्था, सुचारु कतार प्रबंधन और डिजिटल निगरानी जैसी सुविधाओं ने श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाया है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच श्रद्धालु अधिक सहजता और सुरक्षित वातावरण में दर्शन कर पा रहे हैं। वाराणसी में बुनियादी ढांचे के विकास ने भी धार्मिक पर्यटन को गति दी है। सड़कों का चैड़ीकरण, बेहतर परिवहन सेवाएं, घाटों का सौंदर्यीकरण और आकर्षक प्रकाश व्यवस्था ने शहर की छवि को नया आयाम दिया। गंगा नदी में शुरू हुई क्रूज सेवाओं ने पर्यटकों को काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नए अंदाज में देखने का अवसर दिया है। धार्मिक पर्यटन के बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। होटल, गेस्ट हाउस, दुकानों और व्यवसायों में तेजी आई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और स्थानीय लोगों की आय में सकारात्मक सुधार देखने को मिला है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काशी का व्यापक कायाकल्प हुआ है।

गोबर आधारित कम्पोस्ट व बायोगैस को बढ़ावा दे रही योगी सरकार

लखनऊ (यूएनएस)। प्रदेश में कृषि और पशुपालन को एकीकृत कर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में योगी सरकार प्रयासरत है। गोबर आधारित कम्पोस्ट, बायोगैस, जीवामृत एवं घनामृत के उत्पादन, उपयोग और विपणन को लेकर व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। पशुपालन एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रदेश की गोशालाओं को उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करते हुए कम्पोस्ट, जीवामृत और अन्य जैविक उत्पादों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए गए हैं।प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को विधानसभा स्थित समिति कक्ष 44 ख में पशुपालन विभाग एवं कृषि विभाग के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर गोबर से कम्पोस्ट, बायोगैस, जीवामृत एवं घनामृत के उत्पादन, उपयोग और विपणन को लेकर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। योगी सरकार की प्राथमिकता किसानों की आय बढ़ाने के साथ मिट्टी की उर्वरता को पुनर्स्थापित करना है। प्रदेश में उपलब्ध गोबर संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग कर बड़े पैमाने पर जैविक खाद का उत्पादन संभव है और इसके माध्यम से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम की जा सकती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश की गोशालाओं को उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करते हुए कम्पोस्ट, जीवामृत एवं अन्य जैविक उत्पादों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाए। प्रदेश में अनुमानित रूप से लाखों मीट्रिक टन कम्पोस्ट उत्पादन की क्षमता मौजूद है, जिसके लिए गोशालाओं, डेयरी इकाइयों और किसानों के स्तर पर समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

न्यूज डायरी

हाईकोर्ट सख्तः जौनपुर के आपराधिक मामले में कार्यवाही पर लगायी रोक

विपक्ष को जारी की गयी नोटिस, अधिवक्ता रानू एवं शशिशेखर ने रखा पक्ष

संवाददाता

जौनपुर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के एक आपराधिक मामले में हस्तक्षेप करते हुये निचली अदालत में लम्बित कार्यवाही को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नन्दप्रभा शुक्ला की पीठ ने रोहित राय उर्फ रोहित यादव द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई करते हुए पारित किया।बता दें कि याचिकाकर्ता रोहित राय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने एसीजेएम प्रथम कोर्ट नम्बर 12 जौनपुर के समक्ष लंबित केस संख्या 571/2025 की पूरी कार्यवाही और वर्ष 2017 में दाखिल की गयी चार्जशीट को रद्द करने की मांग की है। यह मामला आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के तहत थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर में दर्ज किया गया था।अधिवक्ताओं के तर्कआवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता रानू जायसवाल एवं शशिशेखर मौर्य ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने दलील दी कि आवेदक शिकायतकर्ता के पति का मित्र है और उसका परिवार से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, इसलिये उसके विरुद्ध अपराध का कोई मामला नहीं बनता है।कोर्ट का निर्देशअदालत ने मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित आदेश जारी किये। कार्यवाही पर रोकः कोर्ट ने निर्देश दिया कि जलालपुर थाने से जुड़े इस केस की पूरी कार्यवाही अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी। नोटिस और जवाबः न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करते हुये राज्य सरकार और अन्य विपक्षी पक्षों से चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा मांगा है। अगली तिथिः मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की गयी है। यह आदेश 23 अप्रैल को न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला द्वारा दिया गया।

डी0एम0 ने निर्माणाधीन कान्हा गौशाला का किया औचक निरीक्षण अधिकारियों को दिए जल्द कार्य पूर्ण करने का निर्देश

मुंगराबादशाहपुर , जौनपुर । स्थानीय नगर के धौरहरा वार्ड में बन रहे कान्हा गौशाला का शनिवार को अपरान्ह जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र ने आकस्मिक निरीक्षण किया । इस दौरान उन्होंने गौशाला के निर्माण व उसमें प्रयुक्त की जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर संतुष्टि जाहिर करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि शीघ्र ही गौशाला का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए । उन्होंने कहा कि जितना जल्दी गौशाला का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा उतना जल्दी यहां अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी । इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष कपिलमुनि , अवर अभियन्ता ओम प्रकाश , अवर अभियन्ता सिविल प्रशान्त राय , राजस्व निरीक्षक रामानुज शुक्ला समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे ।

दबंगों ने घर में घुसकर मचाया ताण्डव, परिवार की पिटाई करके महिला से की अभद्रता

संवाददाता

सुइथाकला, जौनपुर। सरपतहाँ थाना क्षेत्र के सवायन गांव में क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि विवाद के बाद दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की और महिला के साथ अभद्रता किया।प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त गांव निवासी शिवानंद दीक्षित क्रिकेट मैच खेल रहे थे तभी उनके साथ मौजूद कुछ युवकों से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर शिवानंद जान बचाकर अपने घर भागे लेकिन आरोपित युवक गाली-गलौज करते हुए उनके पीछे-पीछे घर में घुस आये। घर में मौजूद हौसिला प्रसाद, शुभम दीक्षित और सविता दीक्षित ने बीच-बचाव करने की कोशिश किया लेकिन आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडा,लोहे की रॉड और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस दौरान शुभम और हौसिला प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गये।आरोप है कि एक हमलावर ने सविता दीक्षित को जमीन पर पटक दिया जिससे उनके पैर में चोट आई। उनके साथ अभद्रता करते हुए कपड़े फाड़ दिए गए और कान का झाला भी छीन लिया गया। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नौ आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी थानाध्यक्ष मो. जियाउद्दीन अंसारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दुकानदार की मौत , परिवार में मचा कोहराम

मुंगराबादशाहपुर , जौनपुर । स्थानीय क्षेत्र के सरोखनपुर मुहल्ले में शनिवार दोपहर लहभग डेढ़ बजे ग्यारह हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 35 वर्षीय नन्हे उर्फ सुधीर चौहान पुत्र त्रिभुवन चौहान की मौके पर ही दर्दनाकमौत हो गयी । बताते हैं कि मृतक की समोसा व नाश्ते की दुकान है , जिसके ऊपर से ग्यारह हजार की हाई वोल्टेज लाइन गुजरी थी अचानक तार टूटकर नीचे गिर गया । तार को प्लास की मदद से हटाने के प्रयास में सुधीर चौहान विद्युत करेन्ट की चपेट में आ गया जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गयी ।घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया । पत्नी और एक बेटे का रो-रोकर बुरा हाल है । सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया । घटना की जानकारी होते हीघटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गयी । स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है ।

तेज रफ्तार पिकप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, चालक वाहन सहित फरार

खेतासराय, जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के मनेछा गांव में एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवक की पहचान ज्ञान चंद निवासी बढौना, शाहगंज के रूप में हुई है। वह किसी कार्य से जौनपुर की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक मनेछा गाँव के पास पहुंची, उसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ज्ञानचन्द सड़क पर गिरकर गम्भीर रूप से घायल हो गये।घटना के बाद आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुँचे और मानवता का परिचय देते हुए घायल को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जहां उनका उपचार जारी है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद पिकअप चालक बिना रूके वाहन सहित फरार हो गया।

जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में आयी शिकायतों को गुणवत्तापूर्वक एवं समयबद्धता के साथ निस्तारित करने के दिए निर्देश

समाधान दिवस में कुल 164 प्रकरण सुनवाई के लिए आयें, 08 प्रकरणों का मौके पर किया गया निस्तारण ,बमरौली उपरहार क्षेत्र के लेखपाल हिमांशु मुखर्जी को कारण बताओं नोटिस जारी करने एवं तहसीलदार सदर और रजिस्ट्रार कानूनगों से स्पष्टीकरण लिए जाने के दिए निर्देश,जिलाधिकारी ने तहसील में पोषण अभियान के अन्तर्गत 3 महिलाओं की गोदभराई एवं 2 बच्चों का कराया अन्नप्राशन

संवाददाता

प्रयागराज। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील सदर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए निर्देशित किया कि जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने शिकायतों का निस्तारण समयबद्धता के साथ गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने के लिए निर्देशित किया है।जिलाधिकारी ने तहसील में पोषण अभियान के अन्तर्गत 3 महिलाओं की गोदभराई एवं 2 बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया।जिलाधिकारी ने सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जनसमस्याओं को सुनते हुए राजस्व, पुलिस एवं अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को प्रकरण की जमीनी स्तर पर जांच कर शिकायतों को गुणवत्तापूर्वक एवं समयबद्धता के साथ निस्तारित करने एवं प्रार्थनापत्रों की समयबद्ध जांच, कार्रवाई एवं समस्याओं के निस्तारण में विलम्ब होने पर सम्बंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।जिलाधिकारी ने कहा कि जनशिकायतों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले बिंदुओं में से एक है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने शिकायतकर्ता का फीडबैक लेने और शिकायतों के निस्तारण से शिकायतकर्ता संतुष्ट भी कराये जाने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में आयें हुए वरासत, अवैध कब्जा व अन्य शिकायतों का शीघ्रता से निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने प्रार्थनापत्रों की अलग-अलग सूची बनाकर सम्बंधित को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने लेखपाल हिमांशु मुखर्जी क्षेत्र बमरौली उपरहार के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने तथा सम्बंधित प्रकरण में सरसरी तौर पर आख्या लगाये जाने पर उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी करने

के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर और रजिस्ट्रार कानूनगों के द्वारा न्यायालय के आदेशों की परवाना अमलदरामद लम्बित रखने के कारण उनका स्पष्टीकरण लिए जाने के निर्देश दिए है।सम्पूरण समाधान दिवस में प्रार्थिनी सन्नो देवी पत्नी स्व0 खखन्दू लाल यादव निवासी जवाहरगंज, ढरहरिया थाना कर्नलगंज के द्वारा ग्राम बघाड़ा जहूरउद्दीन में आराजी संख्या 399/1 व आराजी संख्या 399/2 के काश्तकारों द्वारा अपने-अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बैनामा करने तथा इसी बैनामें की आड़ में सहखातेदारों द्वारा सरकारी जमीन आराजी संख्या-395/2 व प्रार्थिनी की भूमि आराजी संख्या 399/2 एवं 398/3 पर भी जबरन कब्जा करने की शिकायत की गयी, जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा उपजिलाधिकारी सदर को राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों की टीम गठित कर प्रकरण की आज ही जांच कराये जाने का निर्देश दिया है। जिसपर उपजिलाधिकारी सदर के द्वारा उक्त प्रकरण की जांच हेतु राम कृष्ण मिश्र-राजस्व निरीक्षक उत्तरी, लेखपाल-हरीश वर्मा, नेहा पाल व आकांक्षा पाण्डेय की टीम गठित कर आज ही प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए है।सम्पूरण समाधान दिवस पर तहसील सदर में कुल 164 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें राजस्व विभाग से सम्बंधित 68, नगर निगम से सम्बंधित-28, पुलिस विभाग 41, अन्य विभागों से सम्बंधित 27 थी, जिनमें से 08 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी ने शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों को आज ही प्राप्त करते हुए उनको निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा है कि शिकायतों का निस्तारण अनिवार्य रूप से निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत हो जाना चाहिए।इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य, अपर जिलाधिकारी (नगर) सत्यम मिश्र, उपजिलाधिकारी सदर अभिषेक सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शिवम सिंह, परियोजना निदेशक भूपेन्द्र कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी जी0पी0 कुशवाहा, जिलापूर्ति अधिकारी सुनील कुमार सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजनः 108 शिकायतों में किसी का निस्तारण

दर्जनों बार शिकायतों के बाद भी नहीं निकल रहा समाधान

संवाददाता

मछलीशह। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में तहसील सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ।जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 108 शिकायतें आईं। किसी भी शिकायत का निस्तारण मौके पर नहीं किया गया। लगातार तहसील और समाधान दिवस पर अपनी फरियाद लेकर आने वाले अधिकांश फरियादियों के चेहरे पर निराशा नजर आ रही थी।जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण गरियांव गांव निवासी भरत मिश्र का कहना है कि शारदा सहायक खंड 39 में बने साइफन खोलने और मेन होल बंद करने की दर्जनों बार शिकायत किया लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ।वहीं घाटमपुर की रूपाली दुबे का आरोप है कि पड़ोसियों के उत्पीड़न से परेशान होकर दर्जनों शिकायत किया लेकिन समाधान नहीं हुआ।आज भी शिकायत किया कि पड़ोसी उसके खेत में आग

लगा दिए जिससे उसका खुद का विद्युत केबल जल गया हफ्तों से विद्युत आपूर्ति बाधित है।जिलाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।जमालपुर के अभिषेक नारायण सिंह ने जमालपुर प्राथमिक विद्यालय जोड़ने वाली सड़क मरम्मत,दारूनपुर के इंद्रमणि पत्थरगड्डी के बाद कब्जा न पाने,बभानियांव की बसंती देवी बैनामे की भूमि पर कब्जा न पाने,मुबारकपुर के पिता रामसुमेर ने अपने ही पुत्र पर उनकी जमीन कब्जा करने और इलाज न कराने की शिकायत किया।सभी शिकायतों को जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को तत्काल निस्तारण करने का निर्देश दिया।भूमि एवं विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतों की अधिकता रही।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया,ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ,क्षेत्राधिकारी प्रतिमा वर्मा,खंड विकास अधिकारी अंजलि भारतीय, एस डी ओ विद्युत आदित्य मार्कण्डेय,अधिशासी अधिकारी विजय कुमार सिंह,तहसीलदार रवि रंजन कश्यप,नायब तहसीलदार संतोष कुमार सहित सभी जिले और तहसील के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित झांकियों की निकली भव्य शोभायात्रा

बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणम् गच्छामि से गूंज उठा पूरा वातावरण

संवाददाता

जौनपुर। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पूर्णिमा को शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित झाँकियों की भव्य शोभायात्रा निकाली गयी। यह शोभायात्रा भण्डारी रेलवे स्टेशन से अहियापुर मोड़, सुतहट्टी चौराहा, कोतवाली चौराहा, चहारसू चौराहा, शाही पुल, ओलन्दगंज चौराहा, जोगियापुर, कलेक्ट्री तिराहा से बौद्ध विहार खरका कालोनी लाइन बाजार थाना के सामने बुद्ध मंदिर पहुंची जहां पूजा अर्चना व विश्व शान्ति की मंगल कामना की गयी। साथ ही खीर वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। शोभायात्रा में महिलाएं, पुरुष, बच्चे अपने हाथों में पंचशील का झण्डा लिये शामिल थे जहां बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणम् गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि के मधुर गूंज से पूरा शहर गूंजायमान हो गया। कार्यक्रम का संचालन

दूधनाथ मौर्य, चन्दन मौर्य, स्वदेश मौर्य, नर्सिंग मौर्य ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर प्रियदर्शी अशोक मिशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मौर्य, संरक्षक राम जियावन मौर्य, अध्यक्ष दिनेश चन्द्र मौर्य, पूनम मौर्य, मीडिया प्रभारी पंकज मौर्य, परमानन्द मौर्य, डा. राजीव रत्न मौर्य, महिला प्रकोष्ठ की ममता मौर्य, मुस्कान मौर्य सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।

मैनेजमेंट गुरू डा. अनिल ने नेहा यादव को किया सम्मानित

पुलिस प्रशिक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने किया था सम्मान

संवाददाता

डोभी, जौनपुर। स्थानीय क्षेत्र के आचार्य बलदेव ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन कोपा–पतरही के डीएवी संस्थान नयनपुर पतरही की पूर्व छात्रा नेहा यादव को मैनेजमेंट गुरु डा. अनिल यादव प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित महाविद्यालय एसोसिएशन एवं विद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों ने सम्मानित किया। नेहा यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण के दौरान 60 हजार आरक्षियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मेडल और ट्रॉफी से नवाजा था। केराकत की इस बेटी और अपने महाविद्यालय परिवार को गौरवान्वित कर अपने माता-पिता, गांव, समाज और प्रदेश का मान-सम्मान बढ़ाया है।इसी होनहार/बहादुर छात्रा के सम्मान में आचार्य बलदेव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सम्मान समारोह रखा गया। मैनेजमेंट गुरु डा. अनिल यादव, मिथिलेश यादव फौजी, विवेक यादव, प्रमोद यादव, दीपू यादव, बबलू

यादव ने इस बहादुर बेटी को माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं मैनेजमेंट गुरु ने कहा कि नेहा यादव महाविद्यालय परिवार के सभी छात्र-छात्राओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। डा. संतोष यादव, डॉ संजय मिश्रा, डा. संजय यादव, डा. अन्नू यादव, राहुल यादव, संतोष गोंड, संत यादव, इंद्रसेन यादव, मनीष यादव, परमेश पाल, राजू यादव, वेद प्रकाश, प्रदीप, अमित यादव, आशीष, देवेश पाण्डेय, ओंकार आदि ने छात्रा को सम्मानित किया। वहीं अपने विद्यालय परिवार से यह सम्मान पाकर नेहा यादव ने सबका आभार व्यक्त किया।

बेसहारा गोवंशों के लिए भूसा दान करने वाले समाजसेवियों का सम्मान

डीएम डॉ. दिनेश चंद सिंह ने प्रशस्ति पत्र व अंगवस्त्र देकर किया सम्मानित

मछलीशहर। तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर बेसहारा गोवंशों के लिए भूसा दान करने वाले समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों को जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद सिंह ने प्रशस्ति पत्र व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों से भी आगे बढ़कर बेसहारा गोवंशों के संरक्षण हेतु भूसा दान करने की अपील की।जिलाधिकारी ने कहा कि बेसहारा गोवंशों की देखभाल और संरक्षण समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे में समाजसेवियों और ग्राम प्रधानों द्वारा किया गया यह योगदान सराहनीय है और अन्य लोगों के लिए प्रेरणास्रोत भी है।

सम्मानित किए गए लोगों में आलोक कुमार उपाध्याय (समाजसेवी) जरौरा 30 कुंतल, आजाद कुमार सरोज (प्रधान) कसेरवा 60 कुंतल, हनुमंत पाण्डेय (समाजसेवी) भटहर 21 कुंतल, अनिल कुमार यादव (प्रधान) कटका 21 कुंतल, संतोष दूबे (समाजसेवी) बटनाहित 40 कुंतल, सुरेश कुमार सरोज (प्रधान) करौदा 15 कुंतल, मृत्युंजय बिन्द (प्रधान) सराय यूसुफ 20 कुंतल, शिवनाथ मौर्य (प्रधान) अमारा 20 कुंतल तथा अभिमन्यु सिंह (मछलीशहर कस्बा) द्वारा 10 कुंतल भूसा दान किया गया।विशेष रूप से अभिमन्यु सिंह ने अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पर भूसा दान किया, जिस पर जिलाधिकारी ने उन्हें बधाई देते हुए उनके इस नेक कार्य की सराहना की।मछलीशहर विकास खंड क्षेत्र में भूसा दान का कुल लक्ष्य 1626.00 कुंतल निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक 1056.00 कुंतल की प्राप्ति हो चुकी है। वहीं भूसा क्रय का लक्ष्य 3862.00 कुंतल है, जिसके सापेक्ष अब तक 1448.00 कुंतल की प्राप्ति दर्ज की गई है।

आधे गांव में नहीं ही सकी चकबन्दी, चारपाई पर मरीज ले जाने को मजबूर

खानापट्टी में चकबन्दी न होने से ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित

सिकरारा, जौनपुर। मंगल ग्रह तक पहुंचने की उपलब्धि हासिल करने वाले देश में उत्तर प्रदेश के जनपद का खानापट्टी गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पिछले 60 वर्षों से ग्रामीण चकबंदी की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन सड़क, खड़ंजा, नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव उन्हें हर दिन परेशान कर रहा है। विशेष रूप से गांव की मल्लाह और यादव बस्ती में रहने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं जहां मरीजों को चारपाई पर लादकर अस्पताल ले जाना पड़ता है।स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि चकबंदी न होने के कारण जमीनों का बंटवारा और व्यवस्थापन अधर में लटका है जिसके चलते सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्य रुके हुए हैं। गांव में पक्की सड़कों और नालियों की कमी के कारण बारिश में कीचड़ और जलभराव की समस्या आम है जिससे आवागमन और भी मुश्किल हो जाता है। आकस्मिक बीमारी के मामलों में एम्बुलेंस न पहुँच पाने के कारण मरीजों को चारपाई पर लादकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। उक्त गांव के पूर्व प्रधान बैजनाथ यादव ने बताया, 'हमारे गांव में न सड़क है, न नाली। बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए चारपाई ही एकमात्र साधन है। चकबंदी के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलते हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता।'उक्त गांव के प्रेम निषाद व ओमनाथ निषाद ने बताया कि चकबंदी न होने से बस्ती तक सड़क व जल निकास की नालियों का निर्माण नही हो पाया, बारिश के दिनों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाय घाट निषाद बस्ती की महिलाओं ने बताया कि बस्ती में सड़क न बनने से बच्चों के शादी में दिक्कत हो रही है। बस्ती का एक युवक पीएसी में जवान है। उसकी शादी तय हुई जब लड़की को पता चला कि उक्त गांव तक जाने को सड़क नहीं है तो उसने साफ इंकार कर दिया।'जौनपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद बाबूराम कुशवाहा से ग्रामीणों ने समस्या बताया तो उन्होंने चकबंदी विभाग से प्रक्रिया शुरू कराने का आश्वासन दिए थे। उनकी पहल पर चकबंदी विभाग ने गांव में खुली बैठक का आयोजन करवाया था। बैठक में ग्रामीणों से चकबंदी के पक्ष और विपक्ष में हस्ताक्षर करवाए गए थे जिसमें एक भी लोगों ने विपक्ष में हस्ताक्षर नहीं किये जिससे लोगों में उम्मीद जगी थी। समय बीतने के साथ मामला ठंडे बस्ते में चला गया।ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय उदासीनता के कारण चकबंदी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। गांव के पूर्व प्रधान डॉ रामचरित्र निषाद, अवधेश निषाद, शैलेश यादव, राहुल यादव, सुशील सिंह, जितेंद्र सिंह, संतोष सिंह, वीरेंद्र यादव, रामहित यादव, अनिल यादव, राम अकबाल यादव, गुरु प्रसाद यादव सहित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग किया कि चकबंदी की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए और गांव में सड़क, नाली, जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उनका कहना है कि जब देश अंतरिक्ष में मंगल तक पहुंच सकता है तो क्या उनके गांव तक सड़क नहीं पहुंच सकती?

अरैल संगम घाट पर सख्त सुरक्षा : नो ड्रोन जोन लागू

प्रयागराज। संगम नगरी के अरैल तट पर भारतीय सेना के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। अरैल घाट पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन को देखते हुए व्यापक सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं। पुलिस आयुक्त जोगिंदर कुमार के निर्देशानुसार शनिवार शाम पांच बजे से 3 मई की रात 12 बजे तक अरैल घाट और उसके आसपास के निर्धारित क्षेत्र को 'नो ड्रोन जोन' घोषित किया गया है। इस अवधि में ड्रोन समेत सभी प्रकार के मानव रहित उड़ान उपकरणों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का ड्रोन उड़ाते पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने और पूरे क्षेत्र में निरंतर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।

स्वदेश भारत न्यूज
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र
स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक स्वदीश कुमार द्वारा स्वदेश भारत पब्लिकेशन ग्राम कनकपुर पोस्ट फतेहगंज जिला जौनपुर (उ०प्र०) 222132 से मुद्रित एंव प्रकाशित ।
सम्पादक
स्वदीश कुमार
मो0 9628825379
संरक्षक संजय गुप्ता
7860079888
उप संरक्षक- आदित्य मौर्या
प्रधान सम्पादक- राकेश मौर्या
उप संम्पादक – नियामअतुल्ला
समाचार संम्पादक- विनय कुमार
सह संपादक- तबरेज नियाजी
कार्यकारी सम्पादक
राजेश गौतम, सतीश चौहान
प्रबन्ध संम्पादक –रंजीत कुमार
@-swadeshbharatnews@gmail-com
समस्त वादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा